

प्रेषक,

महिमा,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-3,

देहरादून, दिनांक: 02 दिसम्बर, 2015

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र अर्थ-1/19856/5क(15)/01/2014-15, दिनांक: 08 अक्टूबर, 2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत वचनबद्ध/अवचनबद्ध योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में आवश्यकतानुसार पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं होने के कारण अनुदान सं० 11-आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 02-माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत संलग्नकों बी०एम०-09 (भाग एक) (कुल 04 बी०एम०-09 प्रपत्रों) में उल्लिखित ब्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाइयों की मानक मदों में रुपये 2467+44+806+12024 हजार = रुपये 15341 हजार, (रुपये एक करोड़ त्रैप्पन लाख इक्वियालिस हजार मात्र) की धनराशि की व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से करते हुए उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में स्वीकृत करते हुए व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (क) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृति दी जा रही है एवं व्यय करते समय विभागीय तथा वित्तीय नियमों/निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। धनराशि का व्यय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के प्रतिबन्धों तथा अन्य वित्तीय नियमों के अधीन कय प्रक्रिया संपादित करते हुए किया जायेगा। कय प्रक्रिया का संपादन सक्षम स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में गठित कय समिति के माध्यम से निविदा की शर्तों के अधीन किया जायेगा।
- (ख) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हों, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- (ग) यह उल्लेखनीय है कि व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- (घ) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 400/XXVII (1) /2015, दिनांक: 01.04.2015 एवं शासनादेश संख्या: 183/XXVII(1)/2012, दिनांक: 28.03.2012 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन किया जायेगा।
- (ङ) मितव्ययिता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।
- (ज) मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 2047/XIV-219 (2006) दिनांक: 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आंगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।



2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 02-माध्यमिक शिक्षा, के अन्तर्गत संलग्नकों (बी0एम0-09) में उल्लिखित सम्बन्धित ब्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: 58(NP)/XXVII(3)2015 दिनांक: 19 दिसम्बर, 2015 में प्राप्त सहमति के अनुक्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीया,

(महिमा)
उप सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 2031 /XXIV-3/15/02(181)2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन।
- 3- आयुक्त, कुमायूँ मण्डल नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 5- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 6- बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
- 7- वित्त अनुभाग-3/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
- 8- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, 23-लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
- 9- एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 10- अनुभाग अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2, 4 एवं 5 उत्तराखण्ड शासन।
- 11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महिमा)

उप सचिव।